ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
संभलपुरः कोयला खदान के लिये पुलिस पहरेदारी में 40 हजार पेड़ काटे

रविवारीय, 15 - 21 दिसंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-19, रांची कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य 2 रूपये

झारखंड राज्य में पर्यावरण, प्रदूषण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक विषयों पर डॉक्युमेंट्री बनाने के लिये संपर्क करें

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

रांची सांसद संजय सेठ ने प्रश्नकाल में जानकारी मांगी

Sanjay Seth, B.P. Ranchi Jharkhand

रांची : सांसद संजय सेठ ने लोकसभा अतारांकित प्रश्नकाल के दौरान पत्र के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से झारखंड के खनन संबंधित जानकारी मांगी उन्होंने जानना चाहा कि झारखंड में विगत 5 वर्ष तथा चालू वर्ष में खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई है तथा सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा देश सहित झारखंड में खानों की संरक्षण के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशालय डी जी एमएस के अनुसार पिछले 5 वर्ष और चालू वर्ष में खनन दुर्घटनाएं में कमी आई है।

सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में हृदय रोग निःशुल्क चिकित्सीय शिविर

रांची :सी.सी.एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, गोपाल सिंह की पहल पर कायाकल्प मॉडल के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर में आगामी 19 दिसम्बर, 2019 को हृदय रोग की जाँच एवं चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की गई है। यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. पी.के. कुचलाकान्ति (कार्डियोलॉजिस्ट) आगामी 19 दिसम्बर, 2019 को दोपहर 12 बजे से केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, कांके रोड़, रांची आयेंगे, जहां वे मरीजों की जाँच करेंगे तथा चिकित्सीय सलाह देंगे।

शहर में नालियां तो बन गयीं लेकिन उसके गंदे जल को ठिकाने लगाने के लिये नदियों तालाबों में बहाया जा रहा है

नालियों की निकासी डैम में क्यों?

मुख्य संवाददाता

रांची : शहर आज भी जलापूर्ति के लिये अपने जलाशयों पर निर्भर करता है और रांची की बड़ी आबादी कांके डैम, रूक्का डैम जैसे जलाशयों के सप्लाई से ही अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहां का भूभाग कही भी समतल नहीं है। इस कारण से शहर में बन रहे नालों का पानी ढलान की ओर बहता है। इस कारण से रांची में नालों और ड्रेनेज सिस्टम को बनाना भी अपने आप में एक चुनौती है। यह एक तथ्य है कि राजधानी में आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरा। करोड़ो खर्च करने के बाद भी बारिश में यहां के सड़कों पर जल जमाव आम बात है।

अभी शहर के कई इलाकों में नालियों का निर्माण तेजी से हो रहा है। रातू रोड के कांके डैम की तरफ की कॉलोनियों में भी नालियों का निर्माण हो रहा है। इससे आम लोगों को तो जलनिकासी की सुविधा प्राप्त हो रही है, पर इस दूषित जल का अंत कांके डैम में ही हो रहा है। जो चिंता का विषय है। सरकार इतने लंबे समय के बाद भी इसके निष्पादन में असफल रही है। सच्चाई तो यह है कि रांची शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था के लिये सरकार के पास जो भी योजनायें हैं वो समझ से परे है। जबकि यहां के ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिये मंत्रियों और नेताओं की टीम विदेश दौरा तक कर चुकी है।

कांके डैम में बहाया जा रहा है नाला

लाखो खर्च के बाद भी बेकार है फिल्टर प्लांट

गोंदा जलाशय के समानांतर ही रातू रोड है। रातू रोड से गोंदा जलाशय की ओर की भूमि ढलान लिये हुये है इस कारण से नालों का बहाव जलाशय की ओर है। जलाशय और रातू रोड के बीच एक से डेढ किमी की दूरी है जिसमें इंद्रपुरी, सुखदेव नगर, देवी मंडपरोड, सरोवर नगर जैसी घनी आबादी वाली कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों से होकर गुजरने वाले नालों का दूषित जल अंततः गोंदा जलाशय तक पहुंचता हैं। अगर यह जलाशय में मिल जाता है तो डैम का जल भी दूषित हो जायेगा। हालांकि इस समस्या से निदान के लिये दशक भर पूर्व गोंदा जलाशय के सरोवर नगर इलाके में एक वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण भी किया गया था ताकि रातू रोड की नालियों से पहुंचने वाले गंदे जल को इसमें फिल्टर कर उसे डैम में बहा दिया जाये। लेकिन लाखो खर्च करने और डैम में पाइपों का जाल बिछाने के बाद भी यह प्लांट चालू नहीं हो सका। इस कारण से अब हाल में बनाये गये

नालों का दूषित पानी अब सीधे डैम में ही बहाया जायेगा।

वाटर लेबलिंग का ध्यान नही

वर्तमान में रांची नगर निगम के सामने एक नयी चुनौती खड़ी हो गयी है। जिन क्षेत्रों में नये नालियों का निर्माण हो रहा है उसमें ठेकेदार बिना वाटर लेबलिंग किये नालियों का निमाण कर दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा कि नाली निर्माण के बाद भी नालियों में जल बहने के बजाय वह सड़क पर बह रहा है और उन कॉलोनियों की स्थिति नारकीय होती जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत करके हम थक चुके हैं लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नही दे रहा है। हालांकि नगर निगम का कहना है अगले कुछ महिनों में शहर के सभी नालियों को दुरूस्त किया जायेगा।

रांची की नालियां हैं जानलेवा

नालियों की निकासी तो बगैर फिल्टर किये जलाशयों में हो ही रहा है साथ ही यहां की खुली नालियां जानलेवा भी है। कुछ महिनो पहले ट्यूशन पढने जा रही एक बच्ची की दुखद मौत इन खुले खतरनाक नाले में गिरने से हो गयी थी। हाल ही में वर्दमान कंपाउंड में भी ऐसा ही वाकया होते होते बचा। जिसमें बच्चे की मां ने जान पर खेल कर उसे बाहर निकाला। आये दिन दुर्घटनायें तो आम बात हैं और नगर निगम इससे बेपरवाह है

कितना प्रदूषणमुक्त हुआ दामोदर नदी?

- **दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं।**
- **तेनुघाट पर बड़ी मात्रा में तरल कचरा नदी में डाला जाता है।**

डॉ. नितिश प्रियदर्शी

रांची : दामोदर नदी भारत और दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नदी को साफ करने और इसे बचाने के लिए कई वादे किए गए हैं। इसके प्रदूषण के मुख्य कारक इस क्षेत्र में कई कोयला कारखाने हैं। ये कोयला कारखाने कथित रूप से दामोदर नदी में खतरनाक तरल पदार्थ डंप करते हैं। झारखंड के बोकारो में तेनुघाट पर बड़ी मात्रा में तरल कचरा नदी में डाला जाता है। यह नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।

नदी के प्रदूषित जल की खपत हजारों लोगों को बीमार और रोगग्रस्त कर रही है। दामोदर के इस प्रदूषण से झरिया कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रभावित हैं।

झारखंड के चंदवा, लातेहार को दामोदर नदी के स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में बराकर, कोनार, बोकारो, हाहारो, जामुनिया, गारी, गुहिया, खड़िया और भीरा दामोदर हैं। सहायक नदियों के इन सेटों में से, बराकर को दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। दामोदर नदी के तट खनिज संसाधनों से समृद्ध माने जाते हैं। इस कारण इसका उद्योगों द्वारा दोहन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, दामोदर बेसिन के ऊपर कई कोयला जनित उद्योग लगे। उनमें से अधिकांश सरकारी स्वामित्व वाले कोक ओवन संयंत्र, कोयला वॉशर, लोहा और इस्पात संयंत्र, ग्लास, जस्ता, सीमेंट संयंत्र और थर्मल पावर प्लांट हैं। इसका संदूषण दोषपूर्ण उत्खनन, प्रकोष्ठ प्रसंस्करण गतिविधियों, तेल, फ्लाई ऐश, जहरीली धातुओं और कोयले की धूल के कारण शुरू हुआ।

अनुचित प्रबंधन, एक लापरवाह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कारण समस्या बढ़ गई जिसने पर्याप्त प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए हैं। दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ आसपास के लोगो के लिए पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थीं। ये लोग धीरे-धीरे दूषित पानी से प्रभावित हो रहे हैं। भले इसे प्रदूषण मुक्त करने का शोर बहुत हुआ, पर दामोदर आज भी प्रदूषित ही है।

स्कूलों में शिक्षा के स्तर का मानक तय हो

संवाददाता

रांचीः मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षा के स्तर का मानक तय करे। उसी मानक के अनुरूप स्कूलों की ग्रेडिंग हो। शिक्षकों के परफार्मेंस का भी वहीं पैमाना बने। उन्होंने सरकारी स्कूलों के प्रमाणीकरण और छात्रों के दसवीं और बारहवीं के बाद उसके करियर से जुड़े पोर्टल को अभिनव प्रयोग बताते हुए कहा कि यह सब होते हुए भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ही उद्देश्य है। शिक्षा विभाग का दायित्व भी यही है कि वह स्कूलों में शिक्षा को कैसे बेहतर करे और उसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और अन्य कमियों को समय रहते दूर करने का प्रयास करे। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय संवर्द्धन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उद्देश्य एक शिक्षित बच्चा है

मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग की सारी कवायद पर कहा कि अंततः उद्देश्य एक शिक्षित बच्चा है। उन्होंने कहा कि

वे खुद एक शिक्षक के पुत्र हैं और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। वे जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की भूमिका शिक्षा जगत में कितनी मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के सरकारी स्कूलों में भी एक समय शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा था। तब वहां की प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर ने स्कूलों को शिक्षण की गुणवत्ता और उसके मानक प्रदर्शन से जोड़ दिया था। परफार्मेंस के आधार पर स्कूलों को ग्रांट मिलने लगा। बेहतर करने वाले स्कूल और शिक्षक ज्यादा मानधन पाने लगें। होड़ लग गई ज्यादा-से ज्यादा मानधन पाने की और स्कूली शिक्षा आदर्श स्तर की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि अभी यहां यह मॉडल लागू नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि शिक्षक हर स्कूल का एक मानक खुद भी तय करें।

स्थानीय रोल मॉडल विकसित करें

मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय रोल मॉडल डेवलप करने पर बल देते हुए कहा कि इससे हर छात्र, शिक्षक और अभिभावक तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसे लेकर ही हर प्रखंड में एक लीडर स्कूल की परिकल्पना की गई है। शैक्षणिक माहौल से युक्त एक ऐसा स्कूल जिसमें सभी छात्र पढ़ना चाहें और अभिभावक पढ़ाना चाहें। एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर खुद आगे बढ़ें। उन्होंने राज्य भर से आए शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों को इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा विभाग के करियर पोर्टल को वक्त की जरूरतों के अनुसार लगातार परिमार्जित करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्रियां जुटाना शिक्षा का मानक नहीं हो सकता।

हटिया - ओरगा सेक्शन का हुआ विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण

रांची : 13 दिसंबर 2019 को मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने हटिया – ओरगा सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री एम एम पंडित भी उपस्थित थे ।अपने निरीक्षण की शुरुआत ओरगा स्टेशन एवं ओरगा रेलवे कॉलोनी से की पश्चात टाटी और कनरवां स्टेशन के बीच पुल संख्या 574, कनरवां – बानो स्टेशन के बीच पुल संख्या 566, बानो स्टेशन, केबिन, पॉइंट्स एवं बानो रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। इसके पश्चात बानो और महाबुआंग रेलवे स्टेशन के बीच पुल एवं कर्व (४१५१) संख्या 36,पकरा और पोकला स्टेशन के बीच समपार फाटक संख्या एचबी 36, पोकला – बकसपुर के बीच पुल संख्या 489, गोविंदपुर स्टेशन, गोविंदपुर स्टेशन में स्थित समपार फाटक संख्या एचबी 24 तथा गोविंदपुर रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने संबन्धित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये तथा संतुष्टि व्यक्त की और जहां सुधार करने की आवश्यकता है वहां सुधार करने के निर्देश भी दिए एवं कर्मचारियों को कार्य के प्रति हमेशा सजग एवं समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज अम्बष्ठ के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सी हेम्ब्रम, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय)अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरडी) ए आर दास, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता एस उरांव, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी चैतन्य सिंह, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महेश्वर सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (जी) कुलदीप कुमार, मंडल वित्त प्रबंधक (इंचार्ज) नीरज कुमार सिंह, मंडल कार्मिक पदाधिकारी (इंचार्ज) एस श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारी और विभागों के निरीक्षक उपस्थित थे।

एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों पर मंडरा रहा है खतरा

मुकेश रंजन सिंह

अमेजन के जंगलों की आग अभी चर्चा में थी । एशिया में भी उष्णकटिबंधीय जंगलों का विनाश खतरनाक मोड़ पर है। इन जंगलों में उन जीवों का शिकार चरम पर है जो फल के बीजों को अपने खाने के दरम्यान चारो ओर फैला देते थे इससे जंगल में खुद ही नये पेड़ उग आते थे। इन जीवों के सफाये के कारण जंगल सिकुड़ रहे हैं जिससे इनके कार्बन को सोखने की क्षमता घटती जा रही है।

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पेड़ के बीजों को फैलाने वाले फल खाने वाले जानवरों में कमी से जंगलों के कार्बन भंडारण में कमी आयी है। एक जंगल में इन प्रजातियों के कम होने से क्षेत्र की कार्बन सोखने की क्षमता में 3 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। पहले यह माना जाता था कि दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में डिफंक्शन से कार्बन की कमी अमेज़न या कांगो बेसिन जैसी नहीं होगी, लेकिन अध्ययन से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा और अवैध पालतू व्यापार के लिए वन्यजीवों का शिकार किया जा रहा है, और यहां के जंगली जानवरों पर भारी संकट है। इससे चिंतित संरक्षणवादियों ने अवैध शिकार को रोकने के लिए और अधिक कार्रवाई का आह्वान किया है। अभी पिछली गर्मियों में, दुनिया अमेज़न वर्षावन के माध्यम से आग की लपटों की चपेट में थी और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइ ऑक्साइड के विशाल मात्रा का उत्सर्जन हुआ। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनों का हश्र भी ऐसा ही हो सकता है। खाओ याई नेशनल पार्क जो बैंकाक से सिर्फ ढाई घंटे की दूरी पर केंद्रीय थाईलैंड में स्थित है में लगभग एक-तिहाई पेड़ों की प्रजातियों का संरक्षण बड़े फल खाने वाले जानवरों से होता है ये जानवर बीज का फैलाव कर नये पौधों के उगने में मदद करते हैं । यदि ये जानवर गायब हो जाते हैं तो इन जंगलों के अस्तित्व पर संकट आ जायेगा। अभी इन जानवरों का शिकार तेजी से हो रहा है। यहां के प्राइमेट्स, विशेष रूप से गिबन्स, इस जंगल में पेड़ों की प्रजातियों की विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं," बैंकॉक के कासेट्स विश्वविद्यालय में प्लांट इकोलॉजी के प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक, विरॉन्ग चैथर्न ने कहा कि जिस प्रकार से ये जंगल खाली हो रहा है वह न केवल कार्बन सोखने की क्षमता बल्कि जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा । वैज्ञानिकों ने प्रयोग के तौर पर 30-हेक्टेयर के एक भूखंड पर से केवल प्राइमेट्स को हटा दिया , और दूसरा सभी बीज बिखेरने वाली जातियों के पशु पक्षियों को को हटा दिया जिसमें गिब्बन, मैकैस, हॉर्नबिल, हिरण, हाथी और भालू शामिल हैं। उन्होंने पाया कि कम से कम 40 प्रतिशत की कमी से कार्बन सोखने में आ गयी । शोधकर्ताओं ने पहले दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में इसी तरह के अध्ययन किए हैं, लेकिन यह एशिया में अपनी तरह का पहला था, जहां पहले यह माना जाता था कि पेड़ की प्रजातियां बीज फैलाव के लिएइन जीवों पर ही निर्भर हैं, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर ग्लोबल डिस्कवरी एंड कंज़र्वेशन साइंस के निदेशक ग्रेग एस्नर ने कहा, "जैव विविधता के मोर्चे पर, दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती हैं। ''कार्बन भंडारण के संदर्भ में, दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में ग्रह पर लगभग किसी भी अन्य वन क्षेत्र की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक कार्बन संग्रहीत होता है। जब अमेजोनियन और कांगोलेस वनों की तुलना की जाती है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई वन जैव विविधता और कार्बन भंडारण में पतन के तत्काल खतरे में हैं। पाम ऑयल कागज की लुगदी और रबर के बागानों के लिए निगमों द्वारा बड़े पैमाने पर समाशोधन, साथ ही क्षेत्र में आम तौर पर स्लेश-एंड-बर्न प्रथाएं, न केवल वनों और जैव विविधता को नष्ट करती हैं, बल्कि वार्षिक धुंध भी पैदा करती हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं।

2015 में, आग ने इंडोनेशिया में 2.6 मिलियन हेक्टेयर (6.4 मिलियन एकड़) भूमि पर धावा बोल दिया और वहां लगभग 16 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि धुंध उत्पन्न होने से सांस की बीमारियों से आधे मिलियन से अधिक लोग बीमार हुये या मारे गए। इस क्षेत्र में विशेष रूप से पाम ऑयल के लिए वनों की कटाई की दर बहुत अधिक है, डेविड एडवर्ड्स, शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय में संरक्षण विज्ञान के एक प्रोफेसर ने कहा, कि वनों का दोहन और विनाश करने वाले संरक्षणवादियों को वनों तक पहुंचने की अनुमति भी देते हैं और ऐसा वे वन्यजीव व्यापार में संलग्न तत्वों को बचा रहे हैं साथ भविष्य के लिये खतरा पैदा कर रहे हैं।

क्या ठग हैं हमारे माननीय?

अब झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने को हैं। चुनावों से ऐन पहले जनता के सामने हाथ जोड़ने वाले ज्यादतर विधायक अब जीत के बाद संभव है शीतनिद्रा में चले जायेंगे। इसके पहले के कुछ महिनों में हम सब ने गौर किया है कि शहर में ताबड़तोड़ गलियों तक की सड़कें और नालियां बनी हैं या कुछ तो अभी तक बन रही है। इनमें से ज्यादतर सड़कें और नालियां ऐसी हैं जिन्हें बनवाने की मांग जनता सालों से अपने विधायक, मंत्री से करती आ रही थी। लेकिन वो सभी अधर में लटके हुये थे या आश्वासन के भरोसे टाले जा रहे थे। ये हमारे माननीयों का पुराना ढर्रा है कि, जनता की बुनियादी जरूरतों की मांग को लटकाये रखो और चुनावों के समय उसे आनन फानन में बनवा कर वोट बटोर लो। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है।

राजधानी रांची में इन चुनावों से कुछ महिनों पूर्व से ताबड़तोड़ बहुत सारे गली मुहल्लों में सड़कों और नालियों का निर्माण हुआ है। ये सभी वर्षों से लंबित थे और जनता से मंत्री जी समूह में आवेदन मांगते थे। आज ये सभी गुणवत्तारहित और बगैर इंजीनियरिंग प्लान के बन रहे हैं। इनमें से ज्यादतर का हश्र साल लगते - लगते खराब होगा। कुछ सड़कों में तो सीमेंट का इतना कम उपयोग हुआ है कि अभी से ही वहां बालू उड़ने लगे हैं। कई जगह तो हाल में बनी नालियां फेल हो चुकी हैं मुहल्लों में जलजमाव हो रहा है। ठिक चुनावों से पहले काम में ये तेजी और गुणवत्तारहित निर्माण में अंतत: जनता का पैसा ही बर्बाद होता है और हमारे माननीय जीतने के बाद चार साल के लिये सो जाते हैं ऐन चुनाव से पहले जगने के लिये

राजधानी के कई मुहल्लों में जलजमाव से वर्षों से नारकीय स्थिति बनी रही है। नगर निगम से लेकर मंत्री तक लोग आवेदन और गुहार लगाते रहे हैं लेकिन सब लंबित था जो एकाएक चुनावों से पहले बनने लगा है। इसके बनने के बाद भी यह सवाल जनता को सोंचना चाहिये कि सालों तक इन जरूरी निर्माणों को वोट के लिये लटकाये रखने से आमजन को जो परेशानियां झेलनी पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है? झारखंड के एक मंत्री खुलेआम कहते हैं कि अगर हमने जनता की हरेक डिमांड पूरी ही कर दी तो फिर जनता के पास किस काम के भरोसे वोट मांगने जायेंगे? उनका ये बयान अपने आप में ही किसी ठग की तरह है। तो क्या वोट के लिये हमारे माननीयों की मंशा हमेशा जनता को किसी न किसी परेशानी में उलझाये रखने की है?अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विजेता माननीय शपथ भी ले लेंगे तो हमें देखना है कि वो शीतनिद्रा में जायेंगे या वादों को पूरा करने में सक्रिय रहेंगे?

जहरमुक्त अन्न की तरफ लौटता समाज

अंबरीश कुमार

बड़े महानगरों में लोग ऑनलाइन बाजार से अब जैविक, प्राकृतिक और मोटे अनाज भी मंगाने लगे हैं। वजह-खेती में खतरनाक कीटनाशकों और उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाना है, जिनसे तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ये वही अनाज हैं, जिन्हें सत्तर के दशक में ग्रामीण और मध्यवर्गीय परिवारों ने छोड़ दिया था। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के ग्रामीण अंचल में मेरा जाना हुआ। यह अंचल अपनी खुशबू के लिए मशहूर काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आपके घर में यह चावल पक रहा हो, तो आसपास के कई घरों तक इसकी खुशबू जाती है। यह देश के एरोमैटिक यानी सुगंधित चावलों में से एक है। पर यह चावल स्थानीय बाजार में भी दो तरह का मिलेगा। एक तो वह चावल है, जो जैविक विधि से यानी बिना रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के उगाया जाता है।

दरअसल यह ज्यादा महंगा होता है और बड़े किसान इसे ज्यादतर अपने इस्तेमाल के लिए बोते हैं। पर जब से प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है, तब से वे कुछ हिस्सा बाजार में भी देने लगे हैं। उनके खेत भी दो तरह के हो गए हैं, एक जिसमें वे अपने घर के लिए प्राकृतिक ढंग से बोते हैं, तो दूसरा जो प्रचलित रासायनिक खेती का तरीका है, उसके लिए। साफ है कि वे खुद रासायनिक फसल से दूरी बना रहे हैं। पर ज्यादा मुनाफा के चलते बाजार में वे रासायनिक उर्वरक से पैदा हुआ अन्न बेचते हैं। यही स्थिति देश के विभिन्न हिस्सों की भी है। देश में कुछ अंचल ऐसे भी हैं, जहां की खेती अगर जैविक नहीं भी है, तो प्राकृतिक जरूर है। इसकी वजह किसानों की गरीबी भी है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज भी रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता। चाहे अल्मोड़ा के आसपास की भट की दाल हो या फिर चंपावत का मशहूर आलू- राजमा हो। इनमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल बहुत कम होता है।

रामगढ़, जो फलपट्टी के रूप में जाना जाता है, वहां भी आड़ू-सेब को छोड़ दें, तो ज्यादातर फल और सब्जियों में वे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस अंचल से जैविक उत्पादों के बारे में जब किसानों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वे जैविक खेती तो नहीं करते हैं, पर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल भी नहीं करते। ऐसे में इस अंचल के कृषि उत्पादों को जैविक भले न माना जाए, पर वह प्राकृतिक ही माने जाएंगे। यही स्थिति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों की भी यही स्थिति है। उनके पास इतना रुपया ही नहीं होता कि वे महंगे कीटनाशक और उर्वरक खरीद पाएं। ऐसे में वे जो भी उगाते हैं, वह रासायनिक खेती से बेहतर होता है। ऐसे अन्न का इस्तेमाल अगर वे करते हैं, तो बड़े शहरों में लोग आर्गेनिक उत्पाद के रूप में भी करते हैं। पर यह बहुत महंगा होता है। जिस जौ को हमारे पूर्वांचल में दो दशक पहले कोई पूछता नहीं था और वह गेहूं के मुकाबले उसके आधे दाम में मिलता था, काफी महंगा बिक रहा है। मुंबई में एक वरिष्ठ पत्रकार करीब ढाई सौ रुपए किलो का जौ हर महीने ऑनलाइन मंगाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वे सरसों का तेल, दाल से लेकर हल्दी-गुड़ आदि भी मंगाते हैं। इसकी कीमत बाजार से ज्यादा तो होती है, पर यह गारंटी भी होती है कि आप शुद्ध अन्न खा रहे हैं। यह जागरूकता हाल के कुछ वर्षों की है।

अब पंजाब के अन्न से लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि समूचा पंजाब रासायनिक खेती के दुष्परिणाम झेल रहा है। ज्यादातर गांवों में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह पंजाब की हरित क्रांति का काला पक्ष है। यही वजह है कि बहुत से लोग अब जैविक अन्न पर जोर देने लगे हैं। पर जैविक अन्न कम उत्पादन की वजह से महंगा पड़ता है। इसका प्रमाण पत्र लेना भी कम झमेले का काम नहीं है। इसकी फीस बहुत छोटे किसानों को महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से वे अपना उत्पाद जैविक उत्पाद के रूप में नहीं बेच पाते हैं। ऐसे में उनका कृषि उत्पाद, जो जैविक होने के बावजूद जैविक उत्पाद के रूप में नहीं बिक पाता, उनके लिए घाटे का सौदा बन जाता है। उदाहरण के लिए अरहर की आम दाल जो बाजार में अस्सी से सौ रुपए किलो बिकती है, वह जैविक दाल के रूप में सवा सौ से डेढ़ सौ रुपए के भाव बिकती है। अगर सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसे इन सब बातों पर गौर करना चाहिए।

दरअसल सेहत को लेकर लोगों में जो जागरूकता बढ़ी है, उसके चलते लोग मोटे अनाज को भी अपने भोजन का हिस्सा बना रहे हैं। जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मंडुआ से लेकर जई-अलसी तक सब इस्तेमाल होने लगे हैं। शहरी इलाकों में लोगों का खानपान बदल रहा है, तो बाजार भी बदल रहा है। अब पैकेट बंद आटे में मल्टी ग्रेन के कई ब्रांड बाजार में आ गए हैं। यह बात अलग है कि गेहूं के आटे में कौन सा अनाज कितना मिलाना चाहिए, इसकी समझ नहीं विकसित हुई है। यही वजह है कि लोग सोयाबीन या अन्य मोटे अनाज की मात्रा भी जरूरत से ज्यादा मिला देते हैं, जिससे वह सेहत को नुकसान भी पहुंचा देता है। मोटा अनाज खाना चाहिए, पर उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए पहाड़ पर जो भट की दाल होती है, उसके आटे की रोटी डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा नुकसान भी दे सकती है। यह एक छोटा सा उदाहरण है।

दरअसल खानपान में अब जो बदलाव आ रहा है, उसे शहरी समाज भी धीरे-धीरे आत्मसात कर रहा है। जैसे कुछ सब्जियां तो लोग खुद घर में उगा लेते हैं, जो रासायनिक खाद से मुक्त होती है। अगर आप फ्लैट में आप रहते हैं, तो आठ-दस गमलों में भी यह प्रयोग हो सकता है। हरी मिर्च, नींबू, धनिया, टमाटर, करी पत्ता, पालक, बैगन, करेला से लेकर तुरई तक आप आसानी से घरों में उगा सकते हैं। किचन वेस्टेज से प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। इससे रोज आप कुछ तो ऐसी सब्जी खा सकते हैं, जो पूरी तरह रासायनिक खाद से मुक्त होगी। गौर करनेवाली बात यह भी है कि आप मोटा अन्न बाजार से खरीद सकते हैं। इनमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग बहुत कम होता है, जबकि अच्छी गुणवत्तावाले महीन अनाज रासायनिक खाद के इस्तेमाल वाले होते हैं। जिस बासमती चावल का चारों तरफ जोर है, वह अमूमन रासायनिक खाद और कीटनाशक से ही तैयार होता है, जबकि किसी भी अंचल के मोटे चावल या एरोमैटिक यानी सुगंधित चावल का इस्तेमाल कर देखें, वे भी पूर्ण गुणवत्ता वाले होते हैं। सिर्फ छतीसगढ़ में ही ऐसी दर्जनों प्रजातियों का धान उपलब्ध है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ जैविक अन्न ही लें। अगर प्राकृतिक ढंग से उगाया गया अन्न भी मिले, तो उसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में तक बहुत से किसान प्राकृतिक खेती कर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक से दूरी बनाने लगे हैं।

डिसक्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं

गांव और गरीबों में भी पसर रहा है मधुमेह

बालमुकुंद

जहां शहर के लोग मधुमेह से डर कर अपने खान पान और दिनचर्या में सुधार ला रहे हैं वहीं गरीब और ग्रामीणों का खान पान बिगड़ रहा है आर्थिक रूप से थोड़ा सा सक्षम होते हीं उनके भोजन व्यवहार में नकल के कारण ऐसी लापरवाही समा गयी है कि वो भी अब मधुमेह जैसी महामारी के शिकार हो रहे हैं। पारंपरिक और पौष्टिक भोजन की जगह अब ग्रामीण इलाकों में भी दिखावे और स्वाद वाले हानिकारक भोजन का उपयोग बढा है।

टेन की चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी पत्रिका लांसेट ने जून 2017 में भारत के 15 राज्यों में मधुमेह के प्रसार के बारे में एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के एक समूह ने यह अध्ययन किया और इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वित्त की व्यवस्था की। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक भारत में 7 फीसदी लोग (15 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर) मधुमेह के शिकार हैं और 10 से 15 फीसदी लोग मधुमेह से पहले की स्थिति (शुरुआती लक्षण खासकर ब्लड शुगर का बढ़ा स्तर) से ग्रसित हैं। एक गरीब देश पर यह कोई छोटा मोटा स्वास्थ्य बोझ नहीं है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि हम एक महामारी की ओर बढ़ रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाले राज्यों में मधुमेह का प्रसार ज्यादा है जबकि बिहार और झारखंड जैसे गरीब राज्यों में यह कम है। उच्च आय स्तर वाले राज्यों दिल्ली और गोवा के नमूनों का अभी इंतजार है। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह की दर कम है। लेकिन इस अध्ययन में सबसे बड़ी चिंता की बात यह सामने आई है कि समृद्घ राज्यों के शहरों में अमीरों की तुलना में गरीबों में मधुमेह के प्रसार की समस्या ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो समृद्घ शहरों में अमीरों ने खाने पीने की अच्छी आदतें सीख ली हैं।

अब गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भोजन की आदत लग रही है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न लोग मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं। अध्ययन में कहा गया, 'यह एक महामारी है जो संक्रमण की स्थिति में है। शहरी इलाकों में मधुमेह की चपेट में आए गरीबों और ग्रामीण इलाकों में इसकी शिकार संपन्न आबादी के मद्देनजर यह स्थिति आसानी से बेकाबू हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भोजन की वजह से हम भोजन की कमी या कुपोषण की स्थिति से जरूरत से अधिक पोषण की तरफ जा रहे हैं। यह ऐसा बदलाव है जिससे हर हाल में बचा जाना चाहिए।

सच्चाई यह है कि भारत को केवल बीमारियों का दोहरा बोझ कहा जा सकता है। हमारे यहां कुपोषण से लेकर हैजा तक गरीबों की सभी बीमारियां हैं। लेकिन साथ ही हमारे पास कैंसर और मधुमेह जैसी संपन्न लोगों की बीमारियां भी मौजूद है। आईसीएमआर अध्ययन से पता चलता है कि गरीबों को अमीरों वाली बीमारियां हो रही हैं लेकिन दु:खद बात यह है कि वे इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। रोकथाम की नीति शुरू करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। हम जानते हैं कि गैर संचारी कही जाने वाली ये बीमारियां हमारी जीवनशैली से जुड़ी हैं। यानी हम जो खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जिस माहौल में रहते हैं, उनसे इन बीमारियां का सीधा संबंध है। यह विषाक्त पदार्थों के विकास के पैकेज का हिस्सा है। यह विकास का ऐसा मॉडल है जहां हम पहले प्रदूषण फैलाते हैं और फिर इसकी सफाई के बारे में सोचते हैं, ऐसा मॉडल जहां हम अपने भोजन में औद्योगिक-रसायन मिलाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भोजन खाते हैं और फिर कसरत करने के लिए जिम जाने या फिर जैविक भोजन खाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस बदलाव से बच नहीं सकते हैं?

क्या हम गरीब लेकिन अस्वस्थ समाज से संपन्न और स्वस्थ समाज की तरफ नहीं जा सकते? हमें एक ऐसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को क्यों हासिल करना चाहिए जिसे छोड़ा जा सकता है? इसमें ही बदलाव की दरकार है। हमें अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच अहम संबंध बनाने की जरूरत है। आज प्रदूषित जल के कारण हमारी नदियां मर रही हैं और यह देश में बच्चों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। महिलाओं के लिए घरों में स्वच्छ ऊर्जा का अभाव है जिससे उन्हें जैव ईंधन में खाना बनाना पड़ रहा है। इससे वे सांस की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रही हैं। साथ ही यह वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है जिससे हवा में जहर घुल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य पर्यावरण का एक सूचक है। अच्छी बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का वास्तविक उत्प्रेरक है। हम तभी पर्यावरण में सुधार के लिए कदम उठाएंगे जब हमें लगेगा कि इससे सीधे तौर पर हमें नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए आज दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों में रोष है। इसका कारण है कि 2017-18 की सर्दियों में जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति (जब प्रदूषण का स्तर बेकाबू हो गया) ने विषाक्त पदार्थों और हमारे शरीर के बीच संबंध को एक तरह से स्पष्टद्द कर दिया है। यह बदलाव को गति देगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एस-डीजी) में बच्चों को केंद्र में रखने की जरूरत है। इसके तहत 2030 तक दुनिया के लिए 13 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हर लक्ष्य का बच्चों से संबंध है और हर लक्ष्य का बच्चे के स्वास्थ्य और इस तरह धरती के स्वास्थ्य से संबंध है। यह सतत विकास लक्ष्यों का मानवीय चेहरा है जो हमारी सफलता या असफलता को परिभाषित करेगा। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को हमारी धरती के स्वास्थ्य के केंद्र में रखा जाना चाहिए। इनमें कोई एकदूसरे के बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता है।

शीशम की पत्तियों से हड्डी जोड़ने वाले शोध को मिला पुरस्कार

शोध से स्पष्ट हुआ है कि शीशम की पत्तियों के अर्क में ऐसे जैविक रूप से सक्रिय तत्व हैं जो हड्डियों को जोड़ने और हड्डी रोगों के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी रोगों के उपचार के साथ-साथ टूटी हड्डियों को तेजी से जोड़ने में मददगार तकनीक के विकास के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ के शोधकर्ताओं को स्टेम इंपैक्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सीडीआरआई के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जैविक रूप से सक्रिय शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) की पत्तियों के अर्क पर आधारित फॉर्मूला विकसित करने के लिए दिया गया है जो हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार में प्रभावी पाया गया है। सिंथेटिक केमिस्ट्री में कई शोधों के बावजूद टूटी हड्डियों को जोड़ने की प्रभावी दवा नहीं खोजी जा सकी है। इस लिहाज से सीडीआरआई की यह खोज महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन से जुड़े सीडीआरआई के शोधकर्ता डॉ राकेश मौर्य के अनुसार ''शीशम की पत्तियों में पाए जाने वाले हड्डी के गठन से संबंधित गुणों के कारण इस शोध में उसका चयन किया गया है। शीशम की पत्तियों में फ्लैवोनॉयड और ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं जिन्हें उनके हड्डियों के गठन से जुड़े गुणों के लिए जाना जाता है। इस शोध से स्पष्ट हुआ है कि शीशम की पत्तियों के अर्क में ऐसे जैविक रूप से सक्रिय तत्व हैं जो हड्डियों को जोड़ने और हड्डी रोगों के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं।''

सीडीआरआई के एक अन्य वैज्ञानिक डॉ संजीव यादव ने बताया कि ''यह एक ऐसा फॉर्मूला है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हर्बल मेडिकामेंट कहते हैं। इस फॉर्मूले को कैप्सूल के रूप में पेश किया गया है। आमतौर पर हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है, जिसमें डेढ़ से दो महीने लग जाते हैं। जबकि इस फॉर्मूले के उपयोग से 14 दिन में टूटी हड्डी जुड़ सकती है। क्लिनिकल ट्रायल में इसे हड्डियों को जल्दी जोड़ने और ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में प्रभावी पाया गया है।''

कैंपा फंड से उत्तराखंड में चालू होगा ''प्रोजेक्ट ऑर्किड''

ऑर्किड धरती के साथ पत्थर, पेड़ या झाड़ियों पर भी पनप जाता है। उत्तराखंड के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में ऑर्किड की कुल 236 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं।

ऑर्किड के फूलों की अलग अहमियत है। ज्यादातर हिमालयी राज्यों में पाए जाने वाले ऑर्किड फूल अपने रंग, खास बनावट और जटिल पुष्प संचरना के चलते बेहद खूबसूरत होते हैं। उत्तराखंड का **प्रोजेक्ट ऑर्किड** आपको आकर्षित करेगा। उत्तराखंड वन विभाग ने कैंपा योजना (कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) के तहत ऑर्किड की अलग-अलग प्रजातियों को सहेजने के लिए प्रोजेक्ट ऑर्किड शुरू किया है।

उत्तराखंड वन विभाग के वन संरक्षक (अनुसंधान) संजीव चतुर्वेदी बताते हैं कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण के लिहाज से अहम ऑर्किड की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वास में सहेजना है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ के गोरी घाटी क्षेत्र के लुमती वन पंचायत में ऑर्किड के फूल लगने शुरू हो गए हैं। यहां 4.25 हेक्टेअर क्षेत्र में ऑर्किड की 36 प्रजातियां सहेजी गई हैं। गोरी घाटी क्षेत्र के अंदर और आसपास के इलाकों में शोधकर्ताओं ने वर्ष 2019 तक ऑर्किड की 127 प्रजातियां चिन्हित की हैं।

फोम से बने माइक्रोप्लास्टिक से समुद्री जीवों पर संकट

शोध से पता चला है कि फूलों की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को अवशोषित करने वाले हरे रंग के फूलों की फोम दुनिया भर में माइक्रोप्लास्टिक की समस्या को बढ़ा रही है। फूलों के फोम जो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और प्लास्टिक में बदल जाता है।

फूलों का फोम एक घने, हल्के और छिद्रयुक्त सामग्री है जिसे लगभग किसी भी आकार में काटा जा सकता है।ऑस्ट्रेलिया स्थित रॉयल मेलबोर्न इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (आरएमआईटी) के एक अध्ययन में पाया गया कि प्लास्टिक के फोम, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जो बहते हुए नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते है। उन्हें मीठे पानी और समुद्री जानवरों द्वारा निगल लिया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

जलवायु संकट पर सजगता में भारत टॉप टेन में

एजेंसिया

जलवायु संकट पर चल रहे सम्मेलन 'कॉप 25' में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) की जो रिपोर्ट जारी हुई है।पर्यावरण की खातिरजलवायु संकट को लेकर सजगता के मामले में भारत दुनिया के दस देशों में शुमार हो गया है।

वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के पैमाने पर भारत की स्थिति भले अच्छी न हो, लेकिन जलवायु संकट को लेकर सजगता के मामले में भारत दुनिया के दस देशों में शुमार हो गया है। स्पेन की राजधानी मेड्रिड में जलवायु संकट पर चल रहे सम्मेलन 'कॉप 25' में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत को उन पहले दस देशों में रखा गया है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जलवायु संकट पर अब तक हुए वैश्विक सम्मेलनों में भारत ने जो प्रतिबद्धता जताई है, उस पर गंभीरता से काम हो रहा है और पेरिस समझौते व क्योटो समझौते पर अमल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। धरती का जलवायु संकट अकेला भारत का खड़ा किया हुआ नहीं है, यह पूरी दुनिया के देशों, खासतौर से विकसित देशों के कृत्यों और लापरवाही का नतीजा है। इसलिए भारत चाह कर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता और न ही अपने हितों की अनदेखी कर सकता है। संतोष की बात यह है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में भारत की जो भागीदारी है, उसमें हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दुनिया ने इस बात को माना भी है। सीसीपीआइ तैयार करते वक्त सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि संबंधित देश

कोयले की खपत को कम करने सहित ऐसे क्या उपाय कर रहे हैं जिनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन न हो। भारत ने पिछले कुछ समय में इस दिशा में जो काम किया है वह उसके निर्धारित लक्ष्य से पंद्रह फीसद ज्यादा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखें तो कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए कई देशों ने गंभीरता दिखाई है। अब तक जो सत्तावन देश सबसे ज्यादा कार्बन उगल रहे थे, उनमें इकतीस देशों ने इसे कम करने के लिए दूसरे विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है और ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हालांकि भारत सहित दूसरे विकासशील देशों के लिए यह कोई आसान काम नहीं है। भारत के लिए यह बहुत ही मु-श्किल है कि कोयले के इस्तेमाल को एकदम से बंद कर दिए जाए। भारत में न सिर्फ घरेलू स्तर पर, बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग हो रहा है। बिजली उत्पादन तो एक तरह से कोयले पर ही निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इंधन रूप में कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। पर पिछले एक दशक में करोड़ों परिवारों पर गैस मुहैया करवा कर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। अगले तीन साल में चालीस फीसद बिजली नए ऊर्जा स्त्रोतों से बनाने का लक्ष्य रखा है।सवाल है कि दुनिया के अमीर देश क्या कर रहे हैं जलवायु संकट से निपटने के लिए। सीसीपीआइ की रिपोर्ट बता रही है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब जैसे अमीर और ताकतवर देशों का रिकार्ड सबसे ज्यादा बदतर है। अमेरिका ने तो पेरिस समझौते से अपने को अलग ही कर लिया। जाहिर है, वह अपने हितों से कोई समझौता नहीं कर रहा। अब तक होता यही आया है कि दुनिया का पर्यावरण बिगाड़ने के लिए विकसित देश विकासशील देशों को ही निशाना बनाते आए हैं। ऐसे में भारत का रुख साफ है कि वह विकसित देशों के दबाव के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयास जारी रखेगा। क्या यह अमेरिका जैसे देशों के लिए सबक नहीं है!

हरियाणा ने सरसो उत्पादन का लक्ष्य बढाया

राजस्थान को टक्कर देने के चक्कर में हरियाणा सरकार ने खरीद एवं उठान की बिना ठोस व्यवस्था किए इस बार सरसों उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य भी इतना कि जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके लिए प्रदेश के सवा लाख किसानों को सरसों बीज के मिनी किट बांटे जा रहे हैं।

एक किट में दो किलो बीज हैं, जिसमें तिलहन की चार किस्में, आरएच-0749,आरएच-0406, आरवीएस-दो व गिराज हैं। हर जिले के लिए अलग-अलग बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरसों उत्पादन में रेवाड़ी हरियाणा में अव्वल है। पिछले साल 64 हजार हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जिससे बढ़ाकर इस बार 70 हजार हेक्टेयर कर दिया गया है। रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा और मेवात भी सरसों का अच्छा उत्पादन होता है।

प्रदेश सरकार ने इस बार सरसों बिजाई का लक्ष्य बढ़ा कर 6 लाख 36 हजार हेक्टेयर कर दिया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष 6.12 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई थी।

रांची रेल मंडल के हटिया मुरी सेक्शन का निरीक्षण

रांचीः 11 दिसंबर 2019 को दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता के प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी जी के द्विवेदी ने रांची रेल मंडल के हटिया - मुरी सेक्शन का निरीक्षण किया ।अपने निरीक्षण में सबसे पहले उन्होंने नामकुम - टाटीसिल्वे स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक संख्या एम एच 22 का निरीक्षण किया. पश्चात टाटीसिल्वे- गंगा घाट के बीच स्थित समपार फाटक संख्या MH 16 एवं गंगा घाट - जोन्हा स्टेशन के बीच स्थित पुल संख्या 269 का निरीक्षण किया। जोन्हा और किता स्टेशनों के बीच प्वाइंट्स तथा पटरियों का निरीक्षण, सिल्ली स्टेशन एवं सिल्ली यार्ड का निरीक्षण, मुरी- हटिया सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी किया रांची में स्थित पी .डब्ल्यू.आई स्टोर, तथा हटिया स्टेशन के पास स्थित चालक एवं गार्ड लॉबी, कोचिंग डिपो, 140 टन क्षमता की क्रेन ,तथा दुर्घटना राहत ट्रेन का निरीक्षण किया । अपने निरीक्षण के दौरान जहा भी उन्हें त्रुटिया नजर आई उन त्रुटियों को यथाशीघ्र दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए ।

सीसीएल "इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019"से सम्मानित

संवाददाता

रांची : वर्ष के तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त कर सीसीएल ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से कंपनी को "बेस्ट कंपनी इन स्पोर्ट्स प्रमोशन (सार्वजनिक उपक्रम)" के वर्ग में दिया गया। यह पुरस्कार फिक्की, फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। "इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019", को केन्द्रीय खेल मंत्री, ओडिसा सरकार तुषारकांती बेहरा ने खेल मंत्री भारत सरकार, किरेन रिजीजू, संदीप सोमानी, फिक्की एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति में सीएमडी सीसीएल गोपाल सिंह को प्रदान किया गया। इस साल के 9वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का थीम 'स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के माध्यम से न्यू इंडिया का निर्माण' था।

इस अवसर विशेष पर सीएमडी गोपाल सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार देश में खेल के प्रोत्साहन और विकास के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयासों का एक सजीव प्रमाण है। मुझे अपनी प्रेरित टीम की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। राष्ट्रीय मानचित्र पर झारखण्ड को खेल क्षेत्र में सर्वोच्चतम स्थान पर लाने के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध है। सीएमडी के कुशल नेतृत्व में सीसीएल झारखंड में खेल को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तन के लिए खेल कि महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्स अकादमी, चक दे झारखंड, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, दिव्यांग स्पोर्ट्स कुछ ऐसे आदर्श पहल हैं, जो सीसीएल के समावेशी विकास बताता है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार झारखंड में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रथम ''एनसीएसटी लीडरशीप अवार्ड'' एवं हाल ही में खेल प्रोत्साहन में किये गये प्रयासों के लिए दिये गये "प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार" के बाद इस वर्ष का यह तीसरा पुरस्कार है।

खेल प्रोत्साहन हेतु सीसीएल को वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय सम्मान

पानी ढोने वाली महिलायें खो देती हैं अपनी सेहत और बच्चे

देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की जरूरत के लिए महिलाओं या लड़कियों को रोजाना दूर-दराज इलाकों से पानी ढोकर लाना पड़ता है। पनिहारन और पनघट की कहानियों में हम इसे सामान्य दैनिक गतिविधि समझ लेते हैं। पानी भरने और ढोने के इस रोजमर्रा के काम में एक भयानक पीड़ा भी छिपी है। पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजीला ने एक शोध प्रकाशित किया है। इस शोध के मुताबिक पानी लाने का काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर न सिर्फ खराब प्रभाव पड़ता है बल्कि यह काम उनके बच्चों की मृत्यु का कारण भी बन जाता है।

शोध के मुताबिक पानी इकट्ठा करने वाले व्यस्कों के बच्चों की मृत्यु का खतरा तो सबसे ज्यादा होता है वहीं, बच्चे यदि खुद पानी एकत्र करने के काम में लगे हैं तो उनकी डायरिया जनित मौत हो सकती है। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य यदि पानी भरने के काम में लगा है तो यह संभावना बेहद कम हो जाती है कि प्रसूति महिला स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल में बच्चे को जन्म देगी। कोई महिला या लड़की यदि पानी भरने या एकत्र करने के काम में लगी है तो न सिर्फ उसके प्रसव पूर्व देखभाल में कमी हो जाती है बल्कि उनके पांच वर्ष से छोटे बच्चों को अकेले ही कई घंटे रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के साथ दुर्घटना या किसी अनहोनी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इस शोध के लिए 41 देशों के 27 लाख लोगों को शामिल किया गया। पहली बार पानी ढोने और स्वच्छ जल की पहुंच, स्वच्छता और माताओं व बच्चों की सेहत के बीच का संबंध जोड़ा गया है। इस संबंध की जांच के लिए यूनिसेफ के संकेतकों और आंकड़ों को भी इस्तेमाल किया गया है। यूईए के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर हंटर और डॉक्टर जो गीर ने इन आंकड़ों का अध्ययन किया है।

केवलादेव से लुप्त हो रही हैं जीव प्रजातियां

एजेंसियां: भरतपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव में रहने वाले जीवों की विविधता में पिछले पांच दशक के दौरान बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है और यहां रहने वाले स्तनधारी जीवों की कई प्रजातियां स्थानीय तौर पर विलुप्त हो चुकी हैं। यह खुलासा भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में हुआ है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार पिछले करीब छह दशक के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले बदलावों का असर यहां रहने वाले वन्य जीवों पर भी पड़ा है। वर्ष 1966 से अब तक यहां रहने वाले जीवों की आठ प्रजातियां स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी हैं। सलीम अली पक्षी-विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय और मनीपाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। बता दें कि कई मांसाहारी एवं शाकाहारी जीवों के विलुप्त होने और प्राकृतिक आवास के स्वरूप में निरंतर हो रहे बदलाव का असर यहां की जैविक विविधता पर पड़ रहा है। पिछले पांच दशक से अधिक समय के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बाघ, तेंदुआ, काला हिरण, स्मूद कोटेड ऑटर, तेंदुआ बिल्ली, देसी लोमड़ी और हनुमान लंगूर समेत कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा सांबर की आबादी भी काफी कम हुई है। जबकि पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान नीलगाय और चीतल जैसे जीवों की संख्या बढ़ने के कारण केवलादेव में रहने वाले खुरदार जीवों की कुल आबादी बढ़ गई है। जीवों की आबादी में होने वाले इस परिवर्तन के लिए स्थलीय एवं नम आश्रय-स्थलों में बदलाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। लगातार पड़ने वाले सूखे के अलावा जलकुंभी, पैसपेलम डिस्टिकम और पी. जूलीफ्लोरा समेत आक्रमणकारी पौधों की इन तीन प्रजातियों से भी यह राष्ट्रीय उद्यान जूझ रहा है। इसके अलावा जानवरों के परस्पर संघर्ष, कटाई, पशुओं की चराई, कैचमेंट एरिया से विषाक्त रसायनों की संभावित मौजूदगी और राजनीतिक उठा पटक के कारण पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण समस्या को बढ़ावा मिला है। अध्ययनकर्ताओं की टीम में शामिल डॉ. एच.एन. कुमार के मुताबिक शाकाहारी वन्य जीव वनों के स्वरूप, उत्पादकता, पोषण चक्र और मिट्टी के ढांचे को प्रभावित करके वनों के पारीस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य जीवों के व्यवहार और उनके जनसांख्यकीय स्वरूप के बारे में जानकारी होने से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और जीवों के संरक्षण से जुड़ी प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। अक्तूबर,2014 से जून, 2015 के दौरान किए गए इस अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1964 में ही तेंदुए के इस क्षेत्र से लुप्त मान लिया गया था। मगर हाल में फिर से तेंदुए के पैरों के निशान यहां पर देखे गए हैं। केवलादेव में बाघ की मौजूदगी के निशान भी मिले थे, जब 1999 में पहली बार एक बाघिन को यहां देखा गया। हालांकि, कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। वर्ष 2010 में एक बाघ रणथंबौर राष्ट्रीय उद्यान से केवलादेव पहुंच गया था, जिसे बाद में सरिस्का ले जाया गया।

रांची रेल मंडल द्वारा प्रकाशित संरक्षा पुस्तिका का विमोचन मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ की मुख्य उपस्थिति में प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी जी के द्विवेदी ने किया।

दवा के अवशेषों से पैदा हुआ नया खतरा

संवाददाता

हम जिन दवाओं का सेवन करते हैं, उसका 30 से 90 फीसद हिस्सा मल और मूत्र के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इन अवशेषों में हमारे द्वारा खाई गई दवाओं के एक्टिव इनग्रेडिएंट्स मौजूद रहते हैं। एक बार जब उन्हें बिना उपचारित किए सीवर और नालियों में बहा दिया जाता है, तो वे हमारे पर्यावरण या लोगों के शरीर में पहुंच जाती हैं। एक्सपायर और इस्तेमाल नहीं की गई दवाओं को भी डंपिंग साइट्स और लैंडफिल में फेंक दिया जाता है।

अब एक नया प्रदूषक तत्व पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। यह तत्व किसी की बीमारी को ठीक करता है, लेकिन इसका बाकी बचा हिस्सा पर्यावरण को बीमार कर रहा है। इससे भी बड़ी बात है कि यह लाखों लोगों को भी बीमार कर रहा है। यह जीवों पर भी असर डाल रहा है, खासकर वन्य जीवों को इससे खतरा है।

यह नया प्रदूषक हमारी दवाओं, या दवा के रसायनों का अवशेष है, जो कि अनियंत्रित और अनुपचारित रह जाता है। ओईसीडी (ऑर्गेनाजेशन फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इंसानों और जानवरों की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 2,000 से अधिक एक्टिव इनग्रेडिएंट्स के एक ''बड़े हिस्से'' को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। एक बार उनके पर्यावरण में पहुंच जाने के बाद उनके खतरे का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। हर साल ज्यादा से ज्यादा ऐसे एक्टिव इनग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है। इस तरह, यह पर्यावरण में ऐसे अनियंत्रित अवशेषों का भंडार बढ़ता जा रहा है।दवा के निर्माण, प्रयोग और निपटान से लेकर दवा बनाने के सभी चरणों में ये अवशेष हमारे पर्यावरण, जैसे जल निकायों, नदियों, हवा और भोजन में शामिल हो रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा स्रोत इंसान के शरीर में दवा के अवशोषण की प्राकृतिक प्रक्रिया है।

उदाहरण के लिए अमेरिका का ही मामला देखें, जहां हर साल मरीजों को दी गई 4 अरब दवाओं का 33 फीसद हिस्सा कूड़े में फेंक दिया जाता है। हमारे सीवेज सिस्टम इस तरह के एक्टिव इनग्रेडिएंट्स को शोधित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जिससे उनकी मौजूदगी ज्यादा व्यापक हो जाती है। अध्ययन के मुताबिक, दुनिया भर में ऐसे अवशेष या एक्टिव इनग्रेडिएंट्स नदी-तालाबों के पानी, जमीन के नीचे के पानी और नल के पानी में पाए गए हैं। इस अअध्ययन में भारत में विभिन्न जल स्रोतों में 31-100 ऐसे अवशेष पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुतबिक, ''चूंकि दवाओं को कम मात्रा में जीवित जीवों (लिविंग ऑर्गेनिज्म) के साथ संपर्क के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे में थोड़ा सा जमावड़ा भी मीठे पानी के पारिस्थिति-तंत्र पर असर डाल सकता है।'' इसका मतलब है कि किसी शख्स द्वारा खाई गई दवा का अवशेष किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, जबकि वह उस बीमारी से पीड़ित नहीं है। आसान शब्द में कहें तो, यह गलत बीमारी के लिए गलत दवा लेने या बिना वजह दवा लेने जैसा है। और इसका बुरा असर होता है। ओईसीडी की रिपोर्ट में एक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि गर्भनिरोधक गोलियों में एक्टिव सब्सटेंस ''मछली और उभयचरों के स्त्रीकरण का कारण बना है।'' इस अध्ययन में आगे कहा गया है कि मनोचिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवा फ़्लूक्सेटिन के अवशेषों ने मछलियों के व्यवहार को बुनियादी रूप से बदल कर उन्हें ''कम जोखिम प्रतिरोधी'' बना दिया। इस तरह के अवशेष रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस) के लिए जिम्मेदार हैं। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से एक करोड़ लोग मौत का शिकार होंगे, जिनमें से ज्यादातर विकासशील देशों में रहने वाले होंगे।

भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पर्यावरण में नुकसान को लेकर इनमें से अधिकांश का अध्ययन नहीं किया गया है। यहां तक कि, हम पर्यावरण में उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ खास जानते भी नहीं हैं।

हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड ,आईआरसीटीसी तथा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का

रांची रेल मंडल में प्रशिक्षण सेमिनार

रांचीः 13 दिसंबर 2019 को रांची स्थित अधिकारी विश्राम गृह के सभाकक्ष में खान पान सेवाओं में विशेषकर खानपान परोसने के दौरान स्वास्थ्य मानकों का एवं स्वच्छता की महत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए रांची रेल मंडल एवं हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड , आईआरसीटीसी तथा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। रांची रेल मंडल के रांची ,हटिया तथा अन्य मुख्य स्टेशनों पर खानपान के स्टॉल उपलब्ध है। तथा रांची मंडल से खुलने वाले कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है,जो और बेहतर, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण हो इन मुख्य उद्देश्यों के लिए इस प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण सेमिनार में मंडल पर कार्यरत स्टॉल संचालक, वेंडर्स एवं ट्रेनों में खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले वेंडर्स उपस्थित थे।

यह प्रशिक्षण सेमिनार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश के दिशा निर्देश के अनुसार किया गया । सेमिनार को सफल बनाने में मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवराज बनर्जी, आईआरसीटीसी के एरिया मैनेजर युवराज मींज, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल ट्रेनर गौरव सिंह, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक जोगेश मान एवं अन्य निरीक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत और चीन ने कहा:दोहा में बताये रास्ते पर चले दुनिया

एजेंसियां: कॉप-25 में भारत और चीन सहित दुनिया के अन्य नेताओं ने जोर देकर कहा है कि सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में किये गए दोहा संशोधन के लक्ष्यों को हासिल करना जरुरी है। साथ ही, 2020 तक देशों के बीच एमिशन में जो खाई है, उसे भर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मेड्रिड में हो रहा यह सम्मलेन समाप्ति के कगार पर है। दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के साथ दुनिया के दो सबसे घनी आबादी वाले देशों ने भी विकसित देशों द्वारा दिए जा रहे अपर्याप्त धन पर चिंता व्यक्त की है। दोहा संशोधन के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को बढाकर 2013 से 2020 के बीच हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे कॉप-8 में अपनाया गया था। यह शिखर सम्मेलन 2012 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था।

यूएनएफसीसीसी के अनुसार, 10 दिसंबर, 2019 तक 135 देशों ने इस संशोधन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जबकि इसको प्रभावी होने के लिए अभी नौ और देशों के समर्थन की जरुरत है। जबकि विडंबना देखिये की इसके लक्ष्यों को हासिल करने की अवधि अगले साल समाप्त हो रही है। भारत के प्रमुख वार्ताकार रवि शंकर प्रसाद ने एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में उन देशों से जल्द ही इसपर अपनी

स्वीकृति देने की अपील की है, जिन्होंने अब तक इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि एमिशन गैप को भी जल्द भर दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार कॉप-25 में किसी भी विकसित देश ने अब तक इसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2023 में हो रही ग्लोबल स्टॉकटेक से पहले इस गैप को भर दिया जाना चाहिए।

प्रसाद ने बताया कि हालांकि 2019 में ग्रीन क्लाइमेट फंड की भरपाई की गई है। कई देशों ने इसमें अपने योगदान को दोगुना कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद यह केवल 68,746 करोड़ रुपये ही था। इसके साथ ही उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में बताये गए कार्बन क्रेडिट के मुद्दे को पेरिस समझौते में नहीं बढ़ाये जाने पर सवाल उठाया है। जो मैड्रिड में विवाद के प्रमुख बिंदुओं में से एक था, जिसके खिलाफ कई देशों जैसे कि फिजी ने आवाज उठायी है। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2020 के बाद के क्रेडिट का मूल्यांकन नहीं करने से इसमें निवेश करने वालों में गलत सन्देश जायेगा और उनके मन में यूएनएफसीसीसी के प्रति अविश्वास पैदा हो जायेगा।

इस मुद्दे पर भारत से सहमत है चीन

भारत की ही तरह चीन के भी वार्ताकार ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि 2020 से पहले लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे उन्हें इसके बाद न उठाया जाये। उनके अनुसार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंस के लिए विकसित देशों द्वारा किये जा रहे प्रयास काफी नहीं हैं। विकसित देशों ने 2020 से पहले अपने उत्सर्जन में कमी करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किये हैं। विकासशील देशों को विकसित देशों से अधिक समर्थन की आवश्यकता है।

भारत और चीन दोनों ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन मार्किट मैकेनिज्म के मुद्दों को उठाया है। उनके अनुसार विकसित देशों को हर मंच पर अलग-अलग एजेंडे के तहत वित्तीय सहायता के मुद्दे के उठाने का मौका मिला है। सेंट लूसिया के शिक्षा मंत्री गेल रिगोबर्ट ने कहा कि 2020 से पहले के स्टॉकटेकिंग का उपयोग जिम्मेदारी से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इसके मुद्दों को पेरिस समझौते से अलग रखना चाहिए। आज दुनिया के सबसे कमजोर तबके को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लाखों करोड़ रुपये की जरुरत है। जिसके बिना वो इस खतरे से नहीं बच सकते।

अफ्रीका ने दिखाई है राह

रवांडा की पर्यावरण मंत्री जीन डी'आर्क मुजावमरिया ने कहा कि बड़े उत्सर्जकों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। साथ ही सबसे कमजोर और कम विकसित देशों के लिए अधिक वित्तीय सहायता देनी होगी। उन्होंने रवांडा के ग्रीन फंड का हवाला देते हुए बताया कि अफ्रीकी देश द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों ने दिखा दिया है कि "कैसे विकास के साथ-साथ, इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज के प्रति कार्रवाई की जा सकती है। इस फण्ड ने 35 परियोजनाओं में करीब 4 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। 57,500 घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का प्रबंध किया है। 19,500 हेक्टेयर भूमि को मिटटी के कटाव से बचाया है। 137,500 से अधिक ग्रीन जॉब्स उपलब्ध कराई हैं, जिसमें से 60 फीसदी महिलाओं के लिए हैं। हालांकि यह सभी बातें मुख्य वार्ता से अलग कही गयी है। वार्ता कक्ष के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कम ही बात की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मैड्रिड में कॉप-25 का आज आखिरी दिन है। ऐसे में इन सभी मुद्दों को हल होने के आसार कम ही हैं। सभी की नजरे उसी और हैं कि क्या यह वार्ता एक मजबूत और महत्वाकांक्षी अंजाम तक पहुंच पाती है या फिर इस बार भी यह मुद्दे अधर में लटके रहेंगे।

फोटो न्यूज

ये कानपुर में सीसामऊ नाला है जो कभी गंगा में गंदगी बहाने का मुख्य नाला था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बंद करवा कर साफ सफाई करवा इसे सेल्फि प्वाईंट बनवा दिया

पुराने का मोह छूटता नहीं:आज बिजली के एक से बढकर एक रोशनी देने वाले बल्ब के युग में लालटेन कब का लुप्त हो चुका है, लेकिन लालटेन की छवि आज भी पसंद है तभी तो बिजली के बल्बयुक्त लालटेन रांची में बेच रहा है ये शख्स

चर ले मेरी बकरियां: बबूल की पत्तियां बकरियों को पसंद होती हैं, अब डाल ऊंची थी तो बच्चों ने डंडे से उसे झुका दिया कि ले चाव से खा

ओड़िसा के संभलपुर में कोयला खदान के लिये काटे 40 हजार पेड़

देवाशीष राय

मुंबई के आरे के जंगलों के बाद अब ओडिशा के संभलपुर में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। यहां भी जंगल के चारों तरफ पुलिस को तैनात कर दिया गया, इसके बाद शुरू हुई पेड़ों की कटाई। एक के बाद एक 40 हजार से ज्यादा हरे-भरे पेड़ काट डाले गए। ये पेड़ ओडिशा के संभलुपर जिले के तालाबिरा गांव में काटे गए। 40 हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई अडानी समूह से जुड़े नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने की है।

40 हजार पुलिस फोर्स लगा कर ग्रामीणों के विरोध के बावजूद काटे पेड़

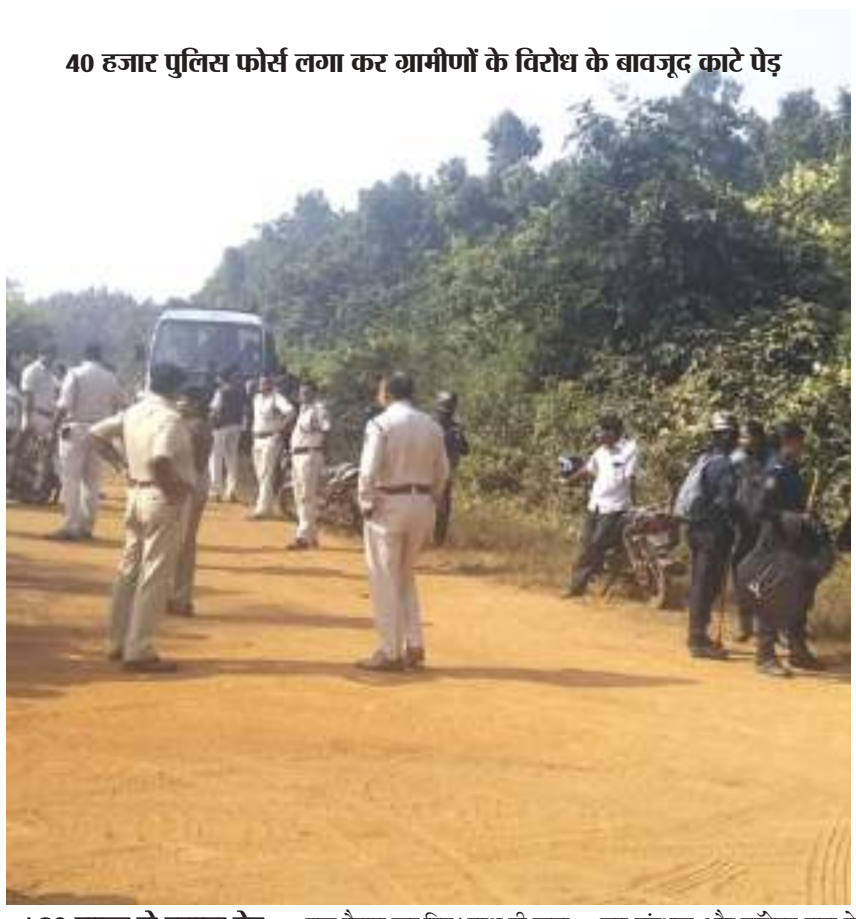

क्यों काटे गए इतने ज्यादा पेड़?

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (NLC) कंपनी यहां कोयले की खदान बनाना चाहती है इसलिए उसने 40 हजार से ज्यादा पेड़ काट डाले। जंगल के चारों तरफ तैनात 10 प्लाटून पुलिस तालाबिरा गांव के इस जंगल के चारों तरफ 10 प्लाटून पुलिस को तैनात करवाकर ठछउ ने पेड़ों की कटाई की। पुलिस इसलिए तैनात की गई ताकि ग्रामीण ज्यादा विरोध न कर सकें। ग्रामीणों ने जताया कड़ा विरोध, पुलिस से भिड़े

पुलिस बल की भारी तैनाती के बावजूद तालाबिरा गांव और आसपास के ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई रोकने का प्रयास किया। विरोध किया। यहां तक कि पुलिस वालों से हल्की झड़प भी हुई लेकिन सब बेकार चला गया। ठछउ ने एक कंपनी के साथ कोयले की खदान बनाने का समझौता कर रखा है। ओडिशा में झारसुगुड़ा और संभलपुर में इसे कोयले की खदान बनानी हैं।

1.30 लाख से ज्यादा पेड़ काटने का दावा

स्थानीय मीडिया के अनुसार यह भी दावा किया जा रहा है कि संभलपुर के चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर 1,30,721 पेड़ काटे गए हैं। कोयला प्रोजेक्ट के लिए पुलिस ने जंगल को घेरा गया लेकिन ग्रामीणों ने फिर भी अतने पेड़ काटने इसका किया था । तालाबिरा ग्राम्य जंगल कमेटी ने जंगल की सुरक्षा के लिए गार्ड तक तैनात कर दिए। साथ ही कहा कि जो भी परिवार इन जंगलों की रक्षा करेगा उसे तीन किलो चावल दिए जाएंगे। जब इस बारे में स्थानीय मीडियाकर्मियों ने संभलपुर के जिलाधिकारी शुभम सक्सेना को फोन करके जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने तत्काल फोन काट दिया। कई बार प्रयास करने पर भी फोन नहीं उठाया। वन मंत्री बिक्रम केशरी अरूख ने फोन पर बात करने की कोशिश भी बेकार गई। ओडिशा के प्रधान वन संरक्षक और फॉरेस्ट बल के प्रमुख डॉ। संदीप त्रिपाठी ने बताया कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

तालाबिरा से निकलता है 2 करोड़ टन कोयला

NLC तालाबिरा-2 और 3 कोल ब्लॉक्स से साल भर में 2 करोड़ टन कोयला का उत्पादन करती है। इससे संभलपुर और झरसुगुड़ा में मौजूद 4200 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट चलते हैं।

सात हजार साल पहले चिलि में हुई थी आर्सेनिक से पहली मौत

चिली के अरीका शहर में 7,000 साल पहले चिंचोरो समुदाय को आर्सेनिक की मार झेलनी पड़ी थी, वहां सबसे पहले एक बच्चे की मौत आर्सेनिक की वजह से हुई थी।

आर्सेनिक प्रदूषण की बात आजकल खूब होती है। भारत में करीब 24 करोड़ लोग यानी करीब 19 प्रतिशत आबादी आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। यह आर्सेनिक आज नहीं बल्कि हजारों साल से लोगों को प्रभावित कर रहा है। 1983 में हुई खुदाई से पता चला कि आर्सेनिक ने हजारों साल पहले लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। खुदाई से मिले प्रमाण बताते हैं कि 7,000 साल पहले चिली के आधुनिक बंदरगाह शहर अरीका से 100 किलोमीटर दूर एक बच्चे की मौत हुई थी। उस बच्चे के माता-पिता ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। उन्होंने बच्चे का सिर और शरीर के अन्य हिस्से अलग कर पशु की खाल में छुपा दिया, सिर पर मिट्टी की एक आकृति बनाई और उसे बालों से सजा दिया। उस साल हुई खुदाई में अरीका के पास स्थित कैमेरोन में 100 से अधिक बच्चों की ममी भी मिलीं। बाद में वयस्कों के भी शव मिले। ये शव चिली के चिंचोरा समुदाय के लोगों के थे।

ट्रिपल खस्सी प्रतियोगिता! बन्द करो ऐसा पुरस्कार

प्रेमसागर सिंह

मुझे एक पुरानी खबर याद आ रही है जिसमें ये लिखा गया था कि रांची के नामकुम में आयोजित ट्रिपल खस्सी प्रतियोगिता ग्रीन गार्डन क्लब ने बेरियस बेक क्लब को 3-2 से हराकर जीत ली। इस प्रतियोगिता में 28 टीमें खेलीं। प्रतियोगिता का इतिहास 37 वर्षो का था। ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन शहर के नजदीक हुआ। ऐसी प्रतियोगिता देहाती एवं वन आच्छादित क्षेत्रो में देखने को मिलते थे। मेरी समझ से इस तरह के पुरस्कार उन दिनों की याद दिलाती है जब लोगो के पास मुद्रा की कमी रही होगी एवं पशुधन की उपलब्धता थी। तब गाँव के प्रधानों ने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने घर के पालतु पशु को उपहार स्वरुप भेंट दिया होगा।

लेकिन आज के परिपेक्ष में जब आम लोग पहले से ज्यादा शिक्षित एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सबल हैं, तब इस तरह से पशुओं के प्रति व्यवहार एवं फुटबॉल प्रतियोगिता में डबल खस्सी प्रतियोगिता/ ट्रिपल खस्सी प्रतियोगिता का आयोजन कहां तक व्यवहारिक हैं? जिस प्रतियोगिता के आयोजन में हीं खून की बू आ रही हो, वह समाज एवं खेल को

कौन मुकाम मिलेगा, ये समय बताऐगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की खस्सी प्रतियोगिता से न तो फुटबॉल का विकास होगा और न तो खिलाड़ियो का। ये सिर्फ खाओ-पिओ मस्त रहो की उक्ति को चरितार्थ करता है। जबकि दूसरी तरफ समाज में पालतु पशुओं के प्रति घृणित व्यहार का समाजीकरण करने का अघोषित प्रयास मात्र है जिसे अबिलम्ब बंद करने की आवश्यता है। ऐसा नहीं कि मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ जिसके चलते ऐसा कृत्य मुझे नहीं भाता, लेकिन ज़रा सोचिए क्या एक शिक्षित समाज को खेल प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसा करना शोभा देता है? अगर पुरस्कार हीं देना है तो उसका स्वरूप तो पूरे विश्व की खेल प्रतियोगिताओं में रोज दिखता है, फिर ये पाषाणयुगी क्रियाकलाप क्यों?

इस तरह के पुरस्कार से खेलों का विकास होने से रहा, दूसरी तरफ नवनिहालों के बाल मन पर भी खेल के प्रति क्या अवधारणा बनेगी, जरा इसकी भी विवेचना कीजिए। चुंकि मैं लम्बे समय तक खिलाड़ी के रूप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हूँ, इसलिए मुझे आज ये पु-रस्कार कहीं चुभता है। पुरस्कार को अब तो सामाचर पत्र भी महिमामंडित करने लगे हैं एवं फोटो के साथ सामाचार का प्रकाशन करने लगे हैं ,जो अशुभ संकेत है इन निरीह पशुओं के प्रति।

नया साल आने को है

E ZONE CARE

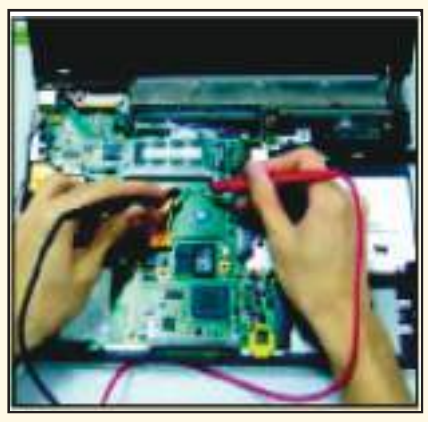

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

आरसीईपीः किसानों पर खतरा बरकरार है

युद्धवीर सिंह

आरसीईपी यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर 2019 को ही इंकार कर चुके हैं। लेकिन अभी भी दूसरे देश यह प्रयास कर रहे हैं कि भारत शामिल हों। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में किसान क्या सोचते हैं?

4 नवंबर 2019 को जैसे ही बैंकॉक से खबर आई कि भारत ने आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया, किसानों की सांस में सांस आई। देश का लगभग हर किसान बैंकॉक में होने जा रहे समझौते पर नजर रखे हुए थे, लेकिन एक बार फिर हमने (किसानों) एक बड़ी लड़ाई जीत ली। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही, स्वदेशी जागरण मंच, किसान संघ का भी, जो इस लड़ाई में किसानों का साथ रहा। अगर यह समझौता हो जाता तो किसानों की बर्बादी शुरू हो जाती। खासकर डेयरी चलाने वाले करोड़ों किसानों के लिए यह समझौता बेहद ही खतरनाक था।

पर इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल चुका है। अब भी भारत को समझौते में शामिल करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है, बल्कि भारत में ही कुछ लोग इस समझौते में शामिल होने के लिए स-रकार पर दबाव बना रहे हैं, इनमें सरकार के मंत्री तक शामिल हैं। इसलिए हम बेहद सचेत हैं और जैसे ही हमें पता चलता है कि भारत फिर से आरसीईपी में शामिल होने के प्रयास कर रहा है तो एक बार फिर देश के सभी किसान संगठन आंदोलन शुरू कर देंगे और इस बार यह आंदोलन पिछले आंदोलन से और बड़ा होगा।

दरअसल, सरकार को यह समझना होगा कि खेती कोई व्यापार नहीं है, एक संस्कृति है। 1948 से लेकर 1995 तक भारत में ऐसा ही माना जाता था और खेती को व्यापार नहीं माना गया, लेकिन 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गेट समझौते के बाद खेती को व्यापार मान लिया गया। हालांकि कृषि क्षेत्र को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुछ आइटम को लेकर देशों के बीच मुक्त व्यापार शुरू हो गया। इसका नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। अब जो सबसे बड़ा सेक्टर आ-रसीईपी में शामिल किया जा रहा था, वह है डेयरी सेक्टर और यदि इसे शामिल कर लिया गया तो भारत के पशुपालकों को अपना यह काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मामले में न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला कर ही नहीं सकते।

कुछ विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि हम अगर कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) मजबूत करते तो हम आरसीईपी में शामिल हो सकते थे, लेकिन किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? दूसरे देशों में कंपनियां खेती कर रही हैं और यूरोप में एक गाय पालने वाले को दो यूरो रोजाना सब्सिडी दी जा रही है। अमेरि-का अपने किसानों को 67 फीसदी सब्सिडी दे रहा है, क्या हम ऐसी सुविधाएं किसानों को दे सकते हैं। जब नहीं दे सकते तो ये विशेषज्ञ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं?

सरकार को चाहिए कि वह कृषि को व्यापार की परिभाषा में शामिल न करे और दुनिया भर के जितने भी देशों से मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है, उन्हें खत्म किसानों की चिंता दूर करे।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 लालगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।